Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 18-05-2006

Participants : Singh Shri Rajiv Ranjan

>

Title : Need to implement the recommendations of National Farmers' Commission for the benefit of farmers in the country.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : महोदय, गत 10 अप्रैल को केन्द्रीय कृाि मंत्री जी के साथ हैदराबाद में 4 राज्य केरल, कर्नाटक, महाराट्र और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुयी , उनकी सोच थी कि इन्हीं प्रदेशों में किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्म हत्यायें करने के लिए विवश हो रहे हैं परंतु वास्तविकता यह है कि न केवल उपरोक्त प्रदेशों की खेती अलाभकारी बन चुकी है परंतु समूचे देश की कृाि अनुपयोगी हो चुकी है। आज देश में प्रत्येक किसान पर 12.585 औसतन कर्जा है। पंजाब और हरियाणा जो समूचे देश को भरण पोाण करते हैं के किसान भी कर्ज के बोझ से दबे हैं, पंजाब में औसत कर्जा 41,576 रूपया है जबकि हरियाणा में किसान पर 26,007 रूपया ऋण है। हाल ही के एक सर्वेक्षण से स्पट हुआ है कि 40 प्रतिशत किसान खेती छोड देना चाहता है। जैसे जैसे खेती के विकास की बात कही जा रही है वैसे वैसे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकारी बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र के तहत खेती को 18 प्रतिशत ऋण देना चाहिए था पर उन्होंने 12 प्रतिशत तक ही कर्ज उपलबध कराया। परिणाम यह हुआ कि किसान को निजी क्षेत्र के कर्जदाता की शरण लेनी पड़ी और उसने 24 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक ब्याज वसूली। सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भी किसान की हालत बिगडी है, विश्व व्यापार संगठन के तहत हमने समझौते किए, कृाि क्षेत्र को अंतराट्रीय बाजार के लिए मुक्त बनाया यूरोप, अमेरिका, जापान अपने किसानों को 1 बिलियन डालर तक सब्सिडी दे रहे हैं और हम खेती की आय पर कर लगाने की बात कर रहे हैं। सरकार सब्सिडी को कम करने के लिए कदम उठा रही है, अगस्त 2005 को राट्रीय किसान आयोग ने किसान और किसानों के जी वन को सुधारने के लिए सुझाव दिए थे, दूसरा अगस्त आ रहा है, आयोग की सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।

मेरा आग्रह है कि सरकार देश के समूचे किसान वर्ग को उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर राहत देने की योजना क्रियान्वित करे और खेती को एक सम्पन्न कार्य का स्वरूप प्रदान करे।